Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

सितम्बर 2022

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- उत्तराखंड में होगा नए ज़िलों का गठन 3
- उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड 3
- कुमाऊँ की सूखती नदियों को सदानीरा बनाएगा पिंडारी ग्लेशियर 4
- मुख्यमंत्री ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को मुख्यमंत्री ट्रॉफी दी और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया 4
- अनाथ बच्चों के लिये शुरू होगी 'बालाश्रय योजना' 5
- देहरादून और रुद्रपुर में खुलेंगे सैनिक स्कूल 5
- नेपाल सीमा तक बनने वाली सड़क पर हाथियों के लिये बनेंगे अंडरपास 6
- उत्तराखंड को 594.75 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी 6
- उत्तराखंड में खेल पुरस्कारों की धनराशि बढ़ी 7
- उत्तराखंड कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण निर्णय 8
- छह युवाओं ने उत्तराखंड में खोजा नया ताल 9
- उत्तराखंड में एक अक्तूबर से शुरू होगी धान की खरीद 10
- उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर अब उत्तराखंड में भी होगा सभी मदरसों का सर्वे 10
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) संशोधन 2022 लागू 10
- उत्तराखंड में लागू होगी नई राजस्व संहिता 11
- प्राथमिक स्तर के बाद अब उच्च शिक्षा में भी लागू हो सकती है नई शिक्षा नीति 11
- उत्तराखंड में स्थापित होगा 100 बेड क्षमता का आयुष ग्राम 12
- भारत-नेपाल के बीच काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास 12
- दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर लगेगा एक फीसदी ग्रीन सेस 13
- उत्तराखंड में होगा राज्य मत्स्य विकास बोर्ड का गठन 13
- उत्तराखंड में दो अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ 14
- राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण-2022: गंगा शहरों की श्रेणी में हरिद्वार को स्वच्छता पुरस्कार 14
- उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 15
- उत्तराखंड के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने देश के दूसरे सीडीएस 15

दृष्टि The Vision

नोट :

उत्तराखंड

उत्तराखंड में होगा नए ज़िलों का गठन

चर्चा में क्यों ?

31 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में नए ज़िलों के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने कहा कि नए ज़िलों के गठन की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है, इसे लेकर शीघ्र ही सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के अंदर जहाँ-जहाँ ज़िलों का पुनर्गठन किया जा सकता है, वहाँ नए ज़िले गठित किये जाएंगे।
- इसके तहत ऋषिकेश, पुरोला, रूड़की, कोटद्वार, काशीपुर, रानीखेत व डीडीहाट शहरों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि गढ़वाल में चार तथा कुमाऊँ मंडल में तीन नए ज़िले बन सकते हैं।
- गौरतलब है कि प्रदेश में वर्तमान में 13 ज़िले हैं। 15 अगस्त, 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सबसे पहले उत्तराखंड में चार ज़िले बनाने का ऐलान किया था। इनमें रानीखेत, डीडीहाट, कोटद्वार और यमुनोत्री शामिल थे।
- अल्मोड़ा ज़िले का पुनर्गठन करके रानीखेत, पिथौरागढ़ ज़िले से डीडीहाट, पौड़ी ज़िले से कोटद्वार और उत्तरकाशी ज़िले से यमुनोत्री ज़िले बनाए जाने प्रस्तावित थे।
- वहीं, मार्च, 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को तीसरी कमिश्नरी बनाने की घोषणा की थी। इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर ज़िले को शामिल किया गया था। इसके बाद अल्मोड़ा को गैरसैंण कमिश्नरी में शामिल करने को लेकर तीखा विरोध शुरू हो गया। इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे और तीरथ रावत के सीएम बनने के बाद यह मसला भी दब गया।

उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

चर्चा में क्यों ?

30 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी दी कि उत्तराखंड में दो महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉमन सिविल कोड को लेकर गठित कमेटी अपना काम कर रही है। ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार जल्द ही इसका प्रारूप सार्वजनिक करेगी।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि भाजपा सरकार आने पर वो उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। 23 मार्च को इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई थी।
- नया कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। हालाँकि, गोवा में भी यह कानून लागू है, लेकिन वहाँ स्वतंत्रता से पहले यह कानून बना था।
- समान नागरिक संहिता का अर्थ है- सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून। किसी भी धर्म या जाति के लिये कोई अलग कानून नहीं होगा। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद सभी धर्म एक ही कानून का अनुसरण करेंगे।

कुमाऊँ की सूखती नदियों को सदानीरा बनाएगा पिंडारी ग्लेशियर

चर्चा में क्यों ?

4 सितंबर, 2022 को पेयजल निगम के मुख्य अभियंता एससी पंत ने बताया कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी की प्रमुख सहायक नदियों को बागेश्वर ज़िले की बैजनाथ घाटी में गोमती नदी, कोसी, लोध और गागास नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, जो अगले 50 साल तक पानी की ज़रूरतों को पूरा करेंगी।

प्रमुख बिंदु

- पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी बागेश्वर और अल्मोड़ा ज़िले की सूखती नदियों को सदानीरा बनाने में मदद करेगी। इससे सात बड़े शहरों की आबादी के अलावा करीब एक हज़ार गाँवों को भी फायदा होगा।
- नदियों को बचाने के साथ-साथ यह योजना पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी। गाँवों से हो रहे पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।
- गौरतलब है कि भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना का ज़िक्र किया था, ताकि योजना को आगे बढ़ाने में केंद्र की मदद ली जा सके। इस योजना में ढाई से तीन सौ करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है।
- योजना के तहत पिंडर नदी व उसकी सहायक नदियों सुंदरढूंगा गाड़ और शंभू गाढ़ (समुद्रतल से 22 सौ मीटर ऊँचाई पर स्थित) से करीब 150 किमी. की डेढ़ मीटर व्यास की पाइप लाइन बिछाकर कुमाऊँ के मल्ला पंया गाँव के निकट (समुद्रतल से ऊँचाई 18 सौ मीटर) तक पानी पहुँचाया जाएगा।
- इन नदियों से लगभग 42 क्यूमेक्स (क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड) पानी गंगा की सहायक अलकनंदा नदी में जाता है। इसमें से पाइप लाइन के ज़रिये डेढ़ से दो क्यूमेक्स पानी कुमाऊँ की तरफ मोड़ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को मुख्यमंत्री ट्रॉफी दी और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया

चर्चा में क्यों ?

5 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को मुख्यमंत्री ट्रॉफी दी और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 'पं. दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार योजना' के तहत इंटरमीडिएट स्तर पर आईपी इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार, ग्लोरियल एचएस डीडीहाट पिथौरागढ़, डीएनपीएसएस स्कूल भतरौजखान अल्मोड़ा एवं हाईस्कूल स्तर पर देवभूमि चिल्ड्रेन एकेडमी एचएसएस संकला रुद्रप्रयाग, ग्लोरिया एचएस डीडीहाट पिथौरागढ़ और एमडीएसपी स्कूल लंबगांव टिहरी गढ़वाल को मुख्यमंत्री ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया।
- उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं परीक्षा में पहले स्थान पर रही एसवीएमआईसी मायापुर हरिद्वार की छात्रा दिया राजपूत, एसपीवीएमआईसी गोपेश्वर चमोली के अंशुल बहुगुणा, विवेकानंद वीएमआईसी मडलसेरा बागेश्वर के सुमित सिंह मेहता एवं एसवीएमआईसी जसपुर ऊधमसिंह नगर के दर्शित चौहान को पुरस्कार मिला।
- हाईस्कूल स्तर पर सुभाष इंटर कॉलेज थौलधार टिहरी गढ़वाल के मुकुल सिल्सवाल, एसएसएस ब्रह्मखाल उत्तरकाशी के आयुष अवस्थी, सुभाष इंटर कॉलेज थौलधार टिहरी के आयुष जुयाल एवं विवेकानंद वीएमआईसी मंडलसेरा बागेश्वर की रबीना कोरंगा को पुरस्कृत किया गया।
- इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिये 22 हज़ार प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट दिये जाएंगे। इसके अलावा एक हज़ार विज्ञान शिक्षकों को राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान बंगलूरू में शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं को और बेहतर ढंग से शिक्षा दी जा सके।

अनाथ बच्चों के लिये शुरू होगी 'बालाश्रय योजना'

चर्चा में क्यों ?

5 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अनाथ बच्चों की कक्षा एक से 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था के लिये राज्य सरकार 'बालाश्रय योजना'शुरू करेगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में शिक्षकों और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएँ-

- मुख्यमंत्री ने कहा कि बालाश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई के साथ ही उन्हें मुफ्त पुस्तकें, स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, मोजे एवं लेखन सामग्री दी जाएगी।
- प्रदेश में दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में पहले चरण में अधिक छात्र संख्या वाले 50 स्कूलों में शिक्षकों के लिये शिक्षक आवास बनाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि से स्कूलों में खेल मैदान तैयार किये जाएंगे।
- संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हाईस्कूल स्तर पर 100 स्कूलों में एकीकृत प्रयोगशाला एवं इंटरमीडिएट स्तर पर 100 स्कूलों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल आदि की प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी।
- पीएम पोषण योजना के तहत छह लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को सप्ताह में एक दिन के स्थान पर अब दो दिन दूध दिया जाएगा।
- राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास एवं नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय छात्रावास में छात्र-छात्राओं की भोजन व्यवस्था के लिये सौ रुपए प्रतिदिन की दर से धनराशि दी जाएगी।
- केंद्रपोषित योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि के अलावा होने वाले व्यय को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- केंद्रीय विद्यालयों की तरह प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के लंबे अवकाश पर रहने के दौरान स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर न पड़े, इसके लिये स्थानीय स्तर पर विषयगत शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।
- निदेशालय स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिये सुझाव प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा।
- प्रधानाचार्य के पास 50 हज़ार रुपए की व्यवस्था रहेगी।

देहरादून और रुद्रपुर में खुलेंगे सैनिक स्कूल

चर्चा में क्यों ?

6 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में देहरादून और रुद्रपुर में सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर मंज़ूरी दी गई। अब इसे मंज़ूरी के लिये केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि देहरादून में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और रुद्रपुर में एएन झा इंटर कॉलेज को सैनिक स्कूल के रूप में चलाने का प्रस्ताव रखा गया है।
- केंद्र सरकार की ओर से देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये राज्यों से मानकों को पूरा करने वाले स्कूलों के प्रस्ताव मांगे गए थे।
- उत्तराखंड में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, देहरादून और एएन झा इंटर कॉलेज, रुद्रपुर सैनिक स्कूल के लिये तकरीबन सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं। दोनों का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। प्रस्ताव भेजे जाने के बाद केंद्र की टीम संबंधित स्कूलों का निरीक्षण करेगी।

नोट :

- गौरतलब है कि प्रदेश में अभी मात्र एक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में है, जिसका पूरा संचालन रक्षा मंत्रालय करता है। हालाँकि रुद्रप्रयाग ज़िले के जखोली में भी सैनिक स्कूल खोलने की कवायद पिछले कई साल से चल रही है। इस स्कूल को मंज़ूरी भी मिल गई थी, लेकिन सैनिक कल्याण और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल की कमी के चलते इस स्कूल के भवन निर्माण का मामला पिछले काफी समय से रुका हुआ है।
- रक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये देशभर के जिन 21 नए सैनिक स्कूलों को खोलने की मंज़ूरी दी थी, उनमें देहरादून के भाऊवाला में स्थित जीआरडी वर्ल्ड स्कूल भी शामिल था, लेकिन स्कूल की मान्यता संबंधी शिकायत पर इसमें प्रवेश को स्थगित रखा गया है।
- सैनिक स्कूल खोलने के लिये मानकों को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से प्रदेश से प्रस्ताव भेजने में देरी हुई। पहले यह बताया गया कि इसके लिये 25 एकड़ भूमि की ज़रूरत होगी, लेकिन बाद में पता चला कि आठ एकड़ भूमि में भी सैनिक स्कूल खुल सकता है। स्थिति स्पष्ट होने के बाद विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया।
- प्रदेश में सैनिक स्कूल खोलने के लिये केंद्र सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। इससे ज़रूरी संसाधन जुटाए जा सकेंगे। हालाँकि, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि चयनित किये गए दोनों स्कूल सैनिक स्कूल के सभी मानकों को पूरा करते हैं।

नेपाल सीमा तक बनने वाली सड़क पर हाथियों के लिये बनेंगे अंडरपास

चर्चा में क्यों?

6 सितंबर, 2022 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक योगेंद्र शर्मा ने बताया कि एनएचएआई की ओर से बनबसा में जगबूड़ा से नेपाल सीमा (चांदनी दुधारा) तक बनाई जाने वाली चार किमी. लंबी सड़क पर वन्यजीवों, खासकर हाथियों के अबाध आवागमन के मद्देनज़र अंडरपास बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- एनएचएआई के परियोजना निदेशक योगेंद्र शर्मा ने बताया कि वन्यजीवों के मूवमेंट के लिये सात सौ पचास मीटर की लंबाई में 25 जगहों पर अंडरपास बनाने की योजना है। संबंधित कार्य को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- एनएचएआई के अधिकारियों का दावा है कि कुमाऊँ में पहली बार वन्यजीवों के मूवमेंट के लिये अंडर पास बनेगा। इस महत्त्वाकांक्षी योजना की टेंडर प्रक्रिया चल रही है।
- गौरतलब है कि नेपाल सरकार चांदनी दुधारा में ड्राईपोर्ट बनवा रही है। इस ड्राईपोर्ट को भारत से जोड़ने के लिये एनएचएआई बनबसा से नेपाल सीमा तक चार किमी. फोरलेन सड़क बनाने जा रहा है।
- एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार शारदा नदी पर पुल भी बनेगा। रेलवे ओवरब्रिज भी तैयार किया जाएगा। यहाँ पर एक संयुक्त जाँच चौकी (इमिग्रेशन, वन, पुलिस, एसएसबी और कस्टम) भी बनाई जाएगी।
- रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने बताया कि आवागमन को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिये प्रयास किया जा रहा है। नेपाल सीमा तक महत्त्वपूर्ण सड़क बनाने की दिशा में कार्य प्रस्तावित है। इस योजना पर 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बागेश्वर-टनकपुर रेलवे लाइन के लिये फाइनल लाइन सर्वे का काम चल रहा है, जिसके दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

उत्तराखंड को 594.75 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी

चर्चा में क्यों?

6 सितंबर, 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्तराखंड को75 करोड़ रुपए के अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी की।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपए के अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
- सिफारिश की गई अनुदान राशि व्यय विभाग द्वारा सिफारिश किये गए राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जाएगी।
- इस छठी किस्त के जारी होने के साथ वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी की गई राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 43,100.50 करोड़ रुपए हो गई है।
- उत्तराखंड को सितंबर 2022 के लिये जारी की गई छठी किस्त 75 करोड़ रुपए है तथा वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य को जारी कुल अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडीजी) 3568.50 करोड़ रुपए है।
- उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि राज्यों के अंतरण पश्चात् राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिये वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है।
- इस अनुदान को प्राप्त करने के लिये राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिये अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

उत्तराखंड में खेल पुरस्कारों की धनराशि बढ़ी

चर्चा में क्यों ?

8 सितंबर 2022 को उत्तराखंड खेल विभाग की ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों के पुरस्कारों की धनराशि में वृद्धि के संबंध में आदेश जारी किया गया। खेल पुरस्कारों की धनराशि में 30 से 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

प्रमुख बिंदु

- खेल निदेशक के आदेश के अनुसार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी को दो करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जबकि रजत पदक विजेता को डेढ़ करोड़ और कांस्य पदक विजेता को एक करोड़ रुपए दिये जाएंगे। ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को पचास लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
- विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेल आदि खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के पुरस्कारों की धनराशि भी बढ़ाई गई है।
- विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ी को तीस लाख, रजत पदक विजेता को 20 लाख, कांस्य पदक विजेता को 15 लाख और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को साढ़े सात लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
- शासनादेश के मुताबिक इन सभी खेलों में पदक के आधार पर जितनी धनराशि तय की गई है, उस खिलाड़ी को देय धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि प्रशिक्षकों को समान रूप से दी जाएगी।
- आदेश में यह भी कहा गया है कि ओलंपिक, विश्वकप, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेलों में चयन के बाद खिलाड़ी को संबंधित प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिये मान्य धनराशि का 20 प्रतिशत पहले ही उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रतिभाग या पदक जीतने पर मिलने वाली धनराशि में इसे समायोजित किया जाएगा। यदि खिलाड़ी संबंधित प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं करता है तो पहले उपलब्ध कराई गई धनराशि लौटानी होगी।
- जूनियर खिलाड़ियों को पुरस्कार की धनराशि सीनियर वर्ग की राशि की आधी और सब जूनियर को उसका एक-चौथाई भाग पुरस्कार के रूप में मिलेगा।

प्रतियोगिता	पदक	धनराशि (पहले)	धनराशि (अब)
ओलंपिक खेल	स्वर्ण	डेढ़ करोड़ रुपए	दो करोड़ रुपए
	रजत	एक करोड़ रुपए	डेढ़ करोड़ रुपए
	कांस्य	50 लाख रुपए	एक करोड़ रुपए
	प्रतिभाग	पांच लाख रुपए	50 लाख रुपए
विश्व चैंपियनशिप	स्वर्ण	20 लाख रुपए	30 लाख रुपए
	रजत	12 लाख रुपए	20 लाख रुपए
	कांस्य	सात लाख रुपए	15 लाख रुपए
	प्रतिभाग	एक लाख रुपए	साढ़े सात लाख रुपए
एशियन चैंपियनशिप	स्वर्ण	15 लाख रुपए	30 लाख रुपए
	रजत	10 लाख रुपए	20 लाख रुपए
	कांस्य	सात लाख रुपए	15 लाख रुपए
	प्रतिभाग	75 हज़ार रुपए	साढ़े सात लाख रुपए

उत्तराखंड कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों?

9 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के तहत 5 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने सहित कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट ने पेपर लीक विवाद से घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पाँच भर्ती परीक्षाएँ रद्द कर दी हैं। अब ये भर्तियाँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके साथ ही 18 नई भर्तियों की ज़िम्मेदारी भी लोक सेवा आयोग को सौंपी गई है। कैबिनेट की बैठक में इसके लिये लोक सेवा आयोग के विनियम में संशोधन पर मुहर लगाई गई।
- बैठक के बाद सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को तीन श्रेणियों में बाँटने का निर्णय लिया गया है।
- कुल 7000 पदों पर भर्ती की ज़िम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी गई है। इनमें 700 पद ऐसे हैं, जिनकी भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। 5340 ऐसे पद हैं, जिनका केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और 1187 ऐसे पद हैं, जिनका विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है।
- सभी भर्तियों के लिये लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी करेगा। इसमें समूह ग से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। जिन अभ्यर्थियों की फीस जमा थी, उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी।
- सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए-
- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में वर्णित सेटबैक एवं भू-आच्छादन के मध्य संगति स्थापित करने के उद्देश्य से 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से कम वाले एकल आवासीय भवन बनाने हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड सरकार के आवास घर के नियम में किसी एक विकल्प को चुनकर अपने भवन बना सकते हैं।
- वित्त विभाग के अंतर्गत जीएसटी बिल को बढ़ावा देने के लिये ग्राहक आनलाइन ईनाम योजना, 'बिल लाओ और ईनाम पाओ' की योजना प्रारंभ की जाएगी।

- शहरी विभाग के अंतर्गत नगर पालिका एवं नगर निगम के लिये एकाउंटिंग मैनुअल में एकरूपता लाने के लिये नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
- खाद्य विभाग के अंतर्गत संयुक्त नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक के लिये सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सृजित 932 पद के लिये योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर अब प्राचार्य पद के लिये 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रधानाध्यापकों एवं प्रवक्ता में से समिति विभागीय परीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।
- तकनीकी शिक्षा प्राविधिक परिषद्, रुड़की के अंतर्गत स्थापित संयुत्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ का नाम 'शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान'किया जाएगा।
- न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिये अधिनियम लाया जाएगा।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 10 पद अनुसेवक के लिये आउटसोर्सिंग से भर्ती करने की अनुमति दी गई।
- राजकीय नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में निर्माण एवं संचालन कार्य पीपीपी मोड से सोसायटी मोड के अंतर्गत किया जाएगा।
- राजस्व विभाग के अंतर्गत रूद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये लगभग छह हेक्टेयर की भूमि आवास विभाग को नि:शुल्क दी जाएगी।
- 17 सितंबर से 24 सितंबर, 2022 तक पूरे प्रदेश में वृहद स्वच्छता अभियान पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें सभी स्कूल, सार्वजनिक स्थल, कार्यालय शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री अपने ज़िले के डीएम के समन्वय से काम करेंगे।
- प्रायोगिक रूप से प्रथम बार राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुमाड़ी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज सुमाड़ी, पौड़ी में तथा राजकीय कन्या इंटर कालेज पोखरी, पौड़ी का विलय राजकीय इंटर कालेज गंगाऊ, पौड़ी में किये जाने का निर्णय लिया गया।
- भूमि और भवन की उपलब्धता के आधार पर पर्वतीय जनपद में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
- आवास विभाग के अंतर्गत एक टाईम सेटेलमेंट योजना को अगले कैबिनेट में रखा जाएगा।

छह युवाओं ने उत्तराखंड में खोजा नया ताल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड में टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जनपद के छह युवाओं ने हिमालय क्षेत्र में नया ताल खोज निकाला है। अभी ताल को कोई नाम नहीं दिया गया है। यह ताल 160 मीटर लंबा व 155 मीटर चौड़ा है।

प्रमुख बिंदु

- गौंडार गाँव के अभिषेक पंवार व आकाश पंवार, गिरीया गाँव के दीपक पंवार, टिहरी-बडियागढ़ के विनय नेगी व ललित मोहन लिंगवाल और खंडाह-श्रीनगर के अरविंद रावत ने बीते 27 अगस्त को गौंडार गाँव से अपने ट्रेकिंग अभियान की शुरुआत की।
- दल में शामिल अभिषेक पंवार ने बताया कि अनाम ताल के चारों तरफ नंदी कुंड, कांछनी ताल, आशीत ताल, मैना ताल स्थित हैं। टिहरी-बडियारगढ़ के विनय सिंह नेगी ने बीते वर्ष जून-जुलाई में गूगल अर्थ में मँहेश्वर-पांडवसेरा-नंदकुंडी-घिया विनायक पास-पनपतिया ट्रेकिंग सर्किट के निकट एक ताल को पाया।
- उन्होंने पूरे ट्रेकिंग सर्किट का डिजिटल मैप तैयार किया और पुराने नक्शों की मदद भी ली। इसके बाद सभी छह युवाओं ने इस अनाम ताल की खोजबीन की योजना बनाई और ताल खोज अभियान शुरू किया। युवा ट्रेकर गूगल अर्थ व पुराने नक्शों की मदद से ताल तक पहुँचे। नया ताल बहुत ही सुंदर व भव्य है।
- युवाओं के अनुसार समुद्रतल से 4350 मीटर की ऊँचाई पर स्थित सूखा ताल से वे ग्लेशियर कैंप स्थल पहुँचे जो समुद्रतल से 5100 मीटर की ऊँचाई पर है। इसके बाद ट्रेकर एक सितंबर को ग्लेशियर कैंप से आगे बढ़ते हुए लगभग डेढ़ सौ मीटर नीचे उतरे जहाँ पर उन्हें यह ताल नज़र आया।
- यह ताल समुद्रतल से 4870 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। ताल की लंबाई 160 मीटर, चौड़ाई 155 मीटर है। ताल के नामकरण को लेकर उस पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा जो प्राचीन ताल व कुंड से सजा हुआ है।

नोट :

उत्तराखंड में एक अक्तूबर से शुरू होगी धान की खरीद

चर्चा में क्यों ?

13 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खरीफ खरीद फसल 2022-23 की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में एक अक्तूबर से धान की खरीद शुरू होगी। खाद्य मंत्री ने कहा कि इस सीजन में धान खरीद का लक्ष्य नौ लाख मीट्रिक टन रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- विभागीय मंत्री ने एक से 15 अक्तूबर तक सरकारी विभागों से धान खरीदने एवं इसके बाद कमीशन एजेंट के माध्यम से किसानों से धान खरीद कराने के निर्देश दिये।
- उन्होंने कहा कि चार एजेंसियों- खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, नैफेड और एनसीसीएफ को धान खरीदने के लिये नामित किया गया है। खरीफ सीजन में करीब 257 खरीद केंद्र खोले गए हैं।
- बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऐसे स्थानीय उत्पाद, जिनका केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, जिनमें मंडुआ, मक्का, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, ज्वार आदि शामिल हैं, इनकी खरीद के लिये एक कार्ययोजना तैयार करें।
- मंत्री ने कहा कि पहाड़ के स्थानीय काश्तकारों की आर्थिकी को मज़बूत करने के लिए यह पहल वरदान साबित होगी। इससे पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही, पहाड़ के किसान भी लाभान्वित होंगे।
- इस साल धान के मूल्य में प्रति क्विंटल 100 रुपए की वृद्धि की गई है। सामान्य धान का मूल्य 1940 रुपए से बढ़ाकर प्रति क्विंटल 2040 एवं ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपए से बढ़ाकर 2060 रुपए घोषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर अब उत्तराखंड में भी होगा सभी मदरसों का सर्वे

चर्चा में क्यों ?

13 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों के कामकाज, गतिविधियों को लेकर आ रही शिकायतों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर अब प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश सरकार को राज्य में संचालित हो रहे इन मदरसों के संबंध में तमाम तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों की सच्चाई का पता लगाने के लिये प्रदेश सरकार ने सभी मदरसों का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। वहीं, समाज कल्याण मंत्री चंदनराम दास तो पहले ही सरकार की मदद से संचालित हो रहे मदरसों की जाँच के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी मदरसों का सर्वे कराने की बात कही है।
- विदित है कि हाल ही में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अवैध निर्माण ढहाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने प्रदेश के गैर-पंजीकृत मदरसों की उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर जाँच की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी उनकी बात का समर्थन किया।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के तहत 419 मदरसे संचालित हैं। इनमें से आधे-से-अधिक बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इनमें केवल 192 मदरसे वित्तपोषित हैं, जो केंद्र एवं राज्य सरकार से मदद ले रहे हैं। 103 मदरसों का संचालन वक्फ बोर्ड कर रहा है, जबकि 500 से अधिक निजी मदरसों के संचालन की भी सूचना है।

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) संशोधन 2022 लागू

चर्चा में क्यों ?

14 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड राजस्व विभाग के अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901) संशोधन 2022 लागू कर दिया है। अब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सहित सभी निकाय क्षेत्रों में पूर्व की भाँति ज़मीनों का दाखिल-खारिज हो सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल की संस्तुति के बाद प्रमुख सचिव हीरा सिंह बोनाल की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया।
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901) संशोधन 2022 के लागू हो जाने से प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में दाखिल-खारिज (म्यूटेशन या नामांतरण) का पेच दूर हो गया है।
- गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम आदेश पारित कर लैंड रेवेन्यू (एलआर) एक्ट में राजस्व विभाग के कार्यों को नगर निकाय की सीमा में म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट, 1975 के तहत कराने के आदेश दिये थे। इसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम बनाने की प्रक्रिया तय की गई है, जबकि 1901 के लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार राजस्व अधिकारी ग्रामीण इलाकों के लिये हैं।
- इसके बाद शहरी क्षेत्रों में भू-राजस्व संबंधी मामलों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खासकर दाखिल-खारिज और भू-त्रुटि सुधार संबंधी मामलों का निपटारा नहीं हो पाने के कारण ये मामले लंबित होते चले गए।
- अब पूर्व की भाँति राजस्व संबंधी मामले, दाखिल-खारिज और भूलेख संबंधी त्रुटि के लिये राजस्व विभाग के अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी बना दिया गया है।

उत्तराखंड में लागू होगी नई राजस्व संहिता

चर्चा में क्यों?

16 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने बताया कि उत्तराखंड में नई राजस्व संहिता (रेवेन्यु कोड) लागू होगी। राजस्व परिषद ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंप दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विधि समिति की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद इसे कैबिनेट को भेज दिया जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद यह विधानसभा में जाएगा। जहाँ से पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा।
- गौरतलब है कि प्रदेश में वर्तमान में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम) 1950 और भू राजस्व अधिनियम लागू हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अधिनियम भी प्रचलन में हैं। ये सभी अधिनियम उत्तर प्रदेश से धारण किये गए हैं।
- समय-समय पर इन अधिनियमों में कुछ उप-धाराएँ जोड़ी गईं, लेकिन राज्य का पूर्ण रूप से अपना रेवेन्यु कोड नहीं बन पाया, जबकि उत्तर प्रदेश ने इन्हें समाप्त करते हुए अपना रेवेन्यु कोड वर्ष 2013 में लागू कर दिया था। अब प्रदेश में लागू सभी अधिनियम को मर्ज करते हुए अपना रेवेन्यु कोड तैयार किया जाएगा।

प्राथमिक स्तर के बाद अब उच्च शिक्षा में भी लागू हो सकती है नई शिक्षा नीति

चर्चा में क्यों?

18 सितंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर के बाद इसी माह उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उच्च शिक्षा में नई नीति की शुरुआत करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फैकल्टी की कमी के चलते वार्षिक परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया था, लेकिन अब इसे समाप्त कर सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें 70 फीसदी पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू रहेगा, जबकि 30 फीसदी पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अपने हिसाब से बदल सकेंगे। पाठ्यक्रम को रोज़गारपरक भी बनाया गया है।

नोट :

- विदित है कि राज्य विश्वविद्यालयों की ओर से नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार किये जाने के लिये माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई थी। उच्च शिक्षा मंत्री को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था।
- इसके अलावा कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति एनके जोशी की अध्यक्षता में दून विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय एवं अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के कुलपतियों को सदस्य नामित कर पाठ्यक्रम निर्माण समिति गठित की गई थी।
- गौरतलब है कि जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति-2020 के तहत 'बाल वाटिका' शुरू की थी। इससे उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने अपने यहाँ नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू की।
- इसके तहत प्राथमिक स्कूल परिसर में चल रहे 4447 आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में शुरू किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी को 'बाल वाटिका' का नाम दिया गया है। इसके लिये अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्तमान में 21 निजी विश्वविद्यालय, तीन डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 12 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हैं।

उत्तराखंड में स्थापित होगा 100 बेड क्षमता का आयुष ग्राम

चर्चा में क्यों?

18 सितंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और निवेश को बढ़ावा देने के लिये 100 बेड क्षमता का आयुष ग्राम स्थापित किया जाएगा। इसके लिये केरल की आर्य वैद्यशाला ने सहमति जताते हुए आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ एमओयू करने की बात कही।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि उत्तराखंड को आयुष हब बनाने की दिशा में हाल ही में आयुर्वेद क्षेत्र में काम कर रही केरल की आर्य वैद्यशाला के प्रतिनिधिमंडल ने हरिद्वार स्थित ऋषिकुल और गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज का दौरा किया और राज्य के साथ मिलकर आयुर्वेद पर शोध कार्यों के लिये विश्वविद्यालय के साथ एमओयू करने पर सहमति जताई।
- प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.), मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, आयुष सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय के साथ बैठक कर आयुर्वेद को बढ़ावा देने के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की।
- राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को पंचकर्म, मर्म चिकित्सा को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही, दैनिक जीवन में सगंध पौध व जड़ी-बूटी के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 179 से अधिक एरोमा और 200 से अधिक जड़ी-बूटी पाई जाती है।
- प्रतिनिधिमंडल में शामिल आर्य वैद्यशाला के सीईओ डॉ. जीसी गोपाला पिल्लई ने आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े 'वेलनेस' शब्द की जगह 'वेलबीइंग' का प्रयोग करने का सुझाव दिया।

भारत-नेपाल के बीच काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास

चर्चा में क्यों?

19 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला के मल्ला छारछुम में भारत-नेपाल के बीच काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- जिस समय छारछुम में प्रस्तावित मोटर पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, ठीक उसी समय नेपाल में वहाँ के वाणिज्य मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बडू ने भी शिलान्यास किया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पुल एक साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। यह पुल 32 करोड़ 98 लाख 40 हज़ार रुपए की लागत से बनेगा।

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत-नेपाल के बीच गडत्त चौकी के बाद छारछुम में बनने वाला यह पुल उत्तराखंड में दूसरा मोटर पुल होगा। इस पुल पर छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहन चल सकेंगे।
- इस पुल के बनने से भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा। इससे भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे। क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार बढ़ने से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।

दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर लगेगा एक फीसदी ग्रीन सेस

चर्चा में क्यों?

19 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर सरकार ग्रीन सेस लगाएगी। इसके लिये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जो कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों पर एक प्रतिशत ग्रीन सेस लगाया जाएगा। इस सेस का इस्तेमाल सड़क सुरक्षा के कार्यों में किया जाएगा। इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जिससे सड़क सुरक्षा मज़बूत होगी।
- परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कमर्शियल वाहनों से एंट्री टैक्स वसूल करता है, लेकिन अब कमर्शियल और निजी वाहनों से एक प्रतिशत ग्रीन सेस वसूला जाएगा। इसके लिये परिवहन विभाग सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है।

उत्तराखंड में होगा राज्य मत्स्य विकास बोर्ड का गठन

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये पहली बार सरकार राज्य मत्स्य विकास बोर्ड का गठन करेगी। सचिव मत्स्य की अध्यक्षता में बोर्ड का ढाँचा तैयार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि प्रदेश में मछली पालन में रोज़गार की बहुत संभावनाएँ हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये पहली बार अलग से बोर्ड बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गए हैं। बोर्ड के माध्यम से मछली पालन योजनाओं का क्रियान्वयन और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंध समिति की बैठक में बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। बोर्ड के ढाँचे का प्रस्ताव बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके बाद मंज़ूरी के लिये कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य में लगभग छह हज़ार मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया जाता है। सरकार ने आने वाले एक साल के भीतर मछली उत्पादन को 11 हज़ार मीट्रिक टन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
- प्रदेश में 11 हज़ार से अधिक लोग मछली व्यवसाय कर रहे हैं। प्रदेश में अभी तक कॉमन कार्प, सिल्वर कॉर्प, रोहू मछली का उत्पादन अधिक है।
- बाज़ार में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार की ट्राउट फिश उत्पादन बढ़ा कर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। प्रदेश सरकार पशुपालन विकास के लिये उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड की तर्ज़ पर अब मछली पालन के लिये अलग से मत्स्य विकास बोर्ड बनाने जा रही है।
- उत्तराखंड में शीर्ष तीन मछली उत्पादक जिले हैं- 1. ऊधमसिंह नगर (2921.349 मीट्रिक टन), 2. हरिद्वार (1424.89 मीट्रिक टन), 3. देहरादून (295.53 मीट्रिक टन)।
- सेस ऐसा होगा कि इससे जनता पर ज़्यादा बोझ न पड़े। दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर को छोड़कर दूसरे राज्यों से आने वाले सभी वाहनों पर यह सेस लगेगा।

- यह ग्रीन सेस वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आधार पर लगाया जाएगा। इसके लिये सभी चेकपोस्ट पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से ही उत्तराखंड की सीमा में घुसने वाले प्रत्येक वाहन का टैक्स चेक किया जा सकेगा। इसके आधार पर वसूली की जाएगी। ग्रीन सेस के लिये व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।

उत्तराखंड में दो अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ

चर्चा में क्यों?

22 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश के 13 ज़िलों की 662 न्याय पंचायतों में दो अक्टूबर से खेल महाकुंभ शुरू होगा।

प्रमुख बिंदु

- खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ देहरादून की रायपुर न्याय पंचायत से उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) करेंगे।
- दो अक्टूबर से शुरू होकर 25 जनवरी, 2023 तक चलने वाले खेल महाकुंभ में विभिन्न आयु वर्गों में प्रतियोगिताएँ होंगी। प्रतियोगिताओं में 8 से 14 वर्ष, 14 से 17 वर्ष और 17 से 21 वर्ष आयु वर्ग में कोई भी खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकता है। न्याय पंचायत, ब्लॉक, ज़िला और राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में दो लाख से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे।
- प्रतियोगिता में पंजीकरण मुफ्त रखा गया है। पंजीकरण ग्राम पंचायतों, प्राथमिक विद्यालयों, जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, युवा कल्याण, खेल एवं शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कराया जा सकता है।
- खेल मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पेंटाथलॉन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें 17 से 21 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस, होम गार्ड आदि के जवान भी प्रतिभाग कर सकेंगे। 1600 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊँची कूद, क्रिकेट, बॉल थ्रो, चिनपअप विधाओं में राज्य के युवाओं को आकर्षित करने के लिये ज़िला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।
- इस वर्ष खेल महाकुंभ 2022 के तहत पारंपरिक खेलों, मुर्गा झपट, अडन्, गुल्ली-डंडा, रस्सा-कस्सी आदि को भी शामिल किया गया है।
- न्याय पंचायत स्तर पर अंडर 14 और 17 वर्ष आयु वर्ग में कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, एथलेटिक्स खेल रखे गए हैं।
- ब्लॉक स्तर पर अंडर 14, 17 और 21 आयु वर्ग में कबड्डी, खो खो, वालीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और बालक वर्ग में फुटबॉल को रखा गया है।
- ज़िला स्तर पर इसी आयु वर्ग में कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बालक वर्ग में फुटबॉल, जूडो, बॉक्सिंग, टेबिल टेनिस, ताइक्वांडो, हैंडबॉल, बास्केटबॉल और कराटे को रखा गया है।
- राज्य स्तर पर कबड्डी, खो-खो, वालीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बालक वर्ग में फुटबॉल, जुडो, बॉक्सिंग, टेबिल टेनिस, ताइक्वांडो, हैंडबाल, बास्केटबॉल, कराटे और हॉकी को रखा गया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण-2022: गंगा शहरों की श्रेणी में हरिद्वार को स्वच्छता पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

27 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में उत्तराखंड के गंगा शहरों की श्रेणी में हरिद्वार को स्वच्छता पुरस्कार के लिये चयनित होने की जानकारी केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से शासन और शहरी विकास निदेशालय को पत्र भेजकर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के मिशन प्रबंधक रविशंकर बिष्ट के अनुसार गंगा शहरों की श्रेणी में राज्य के 15 नगर निकाय शामिल थे। इनमें से हरिद्वार को पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है। इसके अलावा देहरादून शहर में भी पिछले वर्ष के आकलन के आधार पर स्थिति में सुधार हुआ है।

- देहरादून को तीन से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की विशेष उल्लेखित श्रेणी में शामिल किया गया है।
- हरिद्वार और देहरादून के साथ ही राज्य में स्वच्छता पुरस्कार के लिये चयनित नगर निकायों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। इससे पहले चार निकायों डोईवाला, नरेंद्रनगर, रामनगर व लंढौर कैंट को स्वच्छता पुरस्कार के लिये चयनित किया गया था।
- शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सौ से कम निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहले तीन राज्यों में शामिल किया गया है।
- इन निकायों को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) एक अक्टूबर को सम्मानित करेंगे।

उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड

चर्चा में क्यों?

27 सितंबर, 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड को प्राप्त हुए बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड के साथ उसे पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिये भी प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ये पुरस्कार ग्रहण किये।
- सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड देश-विदेश के सैलानियों को प्रदेश में आने का निमंत्रण देता है और पर्यटन की सभी श्रेणियों में सुविधाएँ व अवसर यहाँ उपलब्ध हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पहाड़ों की रानी मसूरी में हेलीकाप्टर के माध्यम से हिमालय दर्शन सेवा भी प्रारंभ की गई है।
- उन्होंने पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की आनलाइन प्रतियोगिता प्रारंभ होने की जानकारी भी दी इसमें 25 लाख रुपए से अधिक के पुरस्कार दिये जाएंगे।
- इसके अलावा यात्रा से जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों (ट्रैवल इन्फ्लुएंसर) के लिये आकर्षक योजना लांच की गई है। इसके तहत अंग्रेजी ही नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं में भी वीडियो बनाने वाले इन व्यक्तियों को विभाग में सूचीबद्ध किया जाएगा।

उत्तराखंड के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने देश के दूसरे सीडीएस

चर्चा में क्यों?

28 सितंबर, 2022 को भारत सरकार ने उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के मूल निवासी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को देश का अगला (दूसरा) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अनिल चौहान उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।
- लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अनेक कमांड, स्टाफ और सहायक पदों पर रहे हैं और जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी उन्हें व्यापक अनुभव रहा है।
- गौरतलब है कि पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद 9 महीनों से देश का यह सबसे बड़ा सैन्य पद खाली था, जिसकी ज़िम्मेदारी अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सौंपी गई है।
- 18 मई, 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्रदान किया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं।

- मेजर जनरल की रैंक में उन्होंने उत्तरी कमान में महत्त्वपूर्ण बारामुला सेक्टर में एक इन्फैंट्री डिवीज़न की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने उत्तर-पूर्व में एक कोर की कमान संभाली और सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ बने तथा मई 2021 में सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति तक पदभार संभाला।
- इन कमांड नियुक्तियों के अलावा वह महानिदेशक, मिलिट्री ऑपरेशंस के प्रभार समेत महत्त्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों पर भी रहे। इससे पहले उन्होंने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन के रूप में भी काम किया। वह 31 मई, 2021 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा।
- सेना में विशिष्ट और शानदार सेवा के लिये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

दृष्टि The Vision